

भाग दो : खण्ड चार

वनोपज का राष्ट्रीय व्यापार

मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969

(मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 9, वर्ष 1969)

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त, 1969 अधि. ब. 21438-इक् कीस अ (प्रा.) मध्य प्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 31 जुलाई 1969 को राष्ट्रपित की अनुमित प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सवर्साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

कितपय वनोपज के व्यापार को, लोकिहत में, विनियमित करने और तदर्थ उस व्यापार में राज्य का एकाधिकार उत्पन्न करने के लिये उपबन्ध करने हेतु अधिनियम। भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में मध्य प्रदेश विधान मण्डल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाय :

धारा 1. संक्षिप्त नाम वि: तार - (1) यह अधिनियम, मध्य प्रदेश अधिनियम, 1969 कहा जावेगा।

(2) इसका वि: तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है।

देश वन उपज (व्यापार विनियमन)

(3) (एक) यह, ऐसे क्षेत्रों में तथा ऐसी वन उपज के सम्बन्ध में तत्काल प्रवृत्त होगा, जिन् हें मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अध्यादेश 1969, जो धारा 23 के अधीन निरः त कर दिया गया है, की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, और

(द) ऐसे अन्य क्षेत्र या क्षेत्रों में तथा ऐसे अन्य वन उपज के सम्बन्ध में तथा ऐसी तारीख या तारीखों से प्रवृत्त होगा या जिसे या जिन् हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करें।

नोट - विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा, विभिन्न क्षेत्रों में वन उपज में प्रवृत्त होने की सूचनायें निम्नानुसार हैं :

अधिसूचना ब.	प्रवृत्त होने का दिनांक	क्षेत्र	वन उपज विशेष
(1) 3544/X/69 21-6-69	दि. 21.6.69	सम्पूर्ण मध्य प्रदेश वन प्रवृत्त बः तर, रायपुर, बिबलासपुर, होशंगाबाद, शहडोल, सीधी, मध्य प्रदेश	महुआ फूल, महुआ बीज कुल लू गोंद, विविध पित
(2) 289-1344-X 1-9-1970 (3) - 70 10-8-70	1-9-1970	सीधी, शहडोल, सरगुजा, (केवल चाँद भरवार वन खण्ड) होशंगाबाद, बैतूल, दुर्ग एवं बः तर राजः विजले	सागौन (टेक् टोना मैडिस) साल (शोरिया रोबः टा) साज (टिमर्नीलिया टोमेन) टोसा बीजा (टारोकार पास)
(3) 706-503-X (3) - 72 दिनांक 12-6-72 पृष्ठ 1734		1. पूरा मध्य प्रदेश 2. पूरा मध्य प्रदेश 3. राजः विजले, सीधी, शहडोल, सरगुजा, (केवल चाँद भरवार वन मण्डल) होशंगाबाद, बैतूल, दुर्ग, तथा बः तर	महुआ फूल, महुआ बीज साज (टिमर्नीलिया टोमेन टोसा)
(4) 30-31-73-3-1 दस/दि. 30-6-73	1 जुलाई 1973	रायसेन, भोपाल, सीहोर, शाजापुर, राजगढ़, विदिशा, सिसवनी, तथा छिन्न दवाडा राजः विजले	सागौन (टेक् टोना माडिस) साल (शोरिया रोबः टा) बीजा (टारोकारपस मारसूपियम), शीशम (डलबर जिज्या लेटिफोलिया की)
(5) 704-503-10 (10)-3-72 दि. 12-6-72 राजपः दि.		राजः विजले सीधी, शहडोल, सरगुजा (केवल चाँद भरवारा वन मण्डल), होशंगाबाद, बैतूल, रायपुर, दुर्ग, तथा बः तर	शीशम (डलबरजिया लेटिफोलिया) इमारती लकड़ी
12-6-72, पृष्ठ 1735			
(6) 1290-896-X 4-72 दि. 14-9-72 राजपः 14-9-72	14.9.72	सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ राजः विजले	सागौन (टेक् टोना माडिस) साल (शोरिया रोबः टा) बीजा (टारोकारपस मारसूपियम), शीशम (डलबरजिया लेटिफोलिया)

(7) 86-73- 1- दस दि. 9-11- 73 राजपS दि. 10-9- 73 पृष्ठ 36	9.11.73	रायपुर, दुर्ग, ब: तर, राजनांदगांव, िबलासपुर, रायगढ़ सरगुजा, जबलपुर, बालाघाट, िछन् दवाडा, नरिसंहपुर, िसवनी, मण् डला, रीवा, सीधी, सतना, पन् ना, शहडोल, पूवर् िनमाड, होशंगाबाद, बैतल टीकमगढ़	सभी ूकार के बाँस
--	---------	---	------------------

1. अधि. ब. 25-28-03 दस-3 दि. 28.6.03 से 1-7-03 से कुल लू को छोड़ अन् य गोंद तथा हरार- िनमुर्क त। 2. शब्द "सभी जाति के बाँस" विधान ब. 5 वर्ष 1974 (दि. 2-2-74) पृष्ठ 161 पर राजपS में ूकाशित से जोड़ा।

(8) 30-16-1974 - X-3-1 दि. 31-8-1974 पृष्ठ 2101	1-9-74	नरिसंहपुर, मण् डला, जबलपुर, खण् डवा	सागौन (टेक् टोना मांिडस) शीशम (डलबरिजया लेटिलोलिया), साल (शोरिया रोब: टा)
(9) 31-9-75 3-1-X दि. 9-12-75 9-12-75 पृष्ठ	9-12-75	राज: व िजले ब: तर, रायपुर, बालाघाट, सीधी, िछन् दवाडा, मण् डला, जबलपुर, राजनांद गांव होशंगाबाद।	साल बीज
(10) 30-37-76- III-K दिनांक 24.9.76 राजपS दि. 24.9.76 पृष्ठ 2867		राज: व िजले रीवा, सतना, सरगुजा, (उत् तर तथा दिक्षण सरगुजा वन मण् डल) इन् दौर, उज् जैन, मंदसौर, रतलाम, देवास, धार, झाबुआ, पिश्चम िनमाड, ग् वालियर, िभण् ड, सम् पूणर् मध् य ूदेश	सागौन (टेक् टोना मांिडस), (शोरिया रोब: टा) बीजा (टिरोकारपस मारसूिपयम) शीशम (डलबिजया लेटीफोलिया) की इमारती खेर (अकेिशिया केटेच् यू)
(11) 30-1-75-3 X- 1 दि. 9-10-75 राजपS दि. 10-10-75 पृष्ठ 2302	10-10-75		

म.ू. (वन उपज) व् यापार िविनयम अधिनियम, 1969 की धारा 22 (क) के अन् तर्गत ूदत् त शिक्तियों का ूयोग करते हुए राज् य शासन एतद्वारा य ह िनदेश देती है िक 1 जुलाई, 2003 के कुल लू गोंद को छोड़कर हरार तथा सम: त ूकार की गोंद, सम् पूणर् मध् य ूदेश के िविनिदर् ट वनोपज नहीं रहेगी।

धारा 2. पिरभाषाएं - इस अधिनियम में जब तक संदर्भ में अन् यथा अपेक्षित न हो

(क) 'अभिकतार्' से अभूेत है, धारा 4 के अधीन िनयुक् त िकया गया अभिकतार्।

(ख) 'कोड' से अभूेत है मध् य ूदेश लैण् ड रेवेन् यू कोड, 1959 (बर्मांक 20, वर्ष 1959)

(ग) 'सिमित' से अभूेत है धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन ूत् येक राज: व आयुक् त के संभाग के िलए गिठत सिमित।

(घ) 'वन उपज' से अभूेत है सभी जाति की, कां ठ, खैर, (कत् था) (केटेच् यू) खिदिर (कुछ),

1. "साल बीज" अधिसूचना ब. 1241/21;;/ दि. 5-5-75, राजपS दि. 5-5-75 पृष्ठ 119 पर ूकाशित से जोड़ा गया।

2. पिरभाषा 'घ' में सभी जाति के अधि ब. 5 वर्ष 1974 (2.2.74) जो राजपS में 2.2.74 के ूकाशित से जोड़ा गया।

कुल लू गोंद, (धावड़ा गोंद, बबूल गोंद, खैर गोंद, साल की राल (Resin), सालई की राल (Salai Resin), रोशा घास, रोशा घास का तेल, सम: त रूप में लाख, चपड़ा, महुआ के फूल, महुआ बीज, (टोली), िनचरोजी, साल बीज, गुठली, हरार और कचिरया, माहुल के पत् ते, माहुल की छाल, फूल बुहारी घास या फूल बुहारी।

(ङ) 'शासकीय पट्टाधारी', से अभूेत है कोड की धारा 181 के अधीन राज् य सरकार से भूमि धारण करने वाला व् यिक्त

(च) 'वन' उपज उगाने वाला व् यिक्त।

(एक) उन क्षेडों में, जो समय-समय पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 (ब. 16, वर्ष 1927) के अधीन आरिक्त या संरिक्त वनों के रूप में गिठत िकए गए हों, उगाई गई या पाई गई वनोपज के संबंध में राज् य सरकार से है, और,

(दो) उपयुक् त (एक) के अन् तर्गत न आने वाले क्षेडों में उगाई गई या पाई गई वन उपज के सम् बन् ध;

(क) राज् य सरकार से है, जहाँ वन उपज कोड की धारा 2 के उपधारा (1) की क् लाज (x-3) में यथा

पिरभाषित दखल रिहत भूमि पर उगाई या पाई जावे।

- (ख) किसी इकाई के अन्तर्गत आने वाले, यथास्थित ऐसे खाते के उधारी या भाड़ेदार (Tenant) या शासकीय पट्टेधारी (Government Lessee) या ऐसी सेवा भूमिधारी (Holder or Service land) से है। जिसमें वन उपज अगती हो या पाई जाती हो या उसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है, जो समय-समय पर उसके माध्यम से ऐसी वन उपज पर हक का दावा करता हो, और
- (ग) किसी ऐसी इकाई में, जिसमें की वन उपज उगती हो या पाई जाती हो, मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1968 (ब. 28, वर्ष 1968) के अधीन भूदान धारक से है और उसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है, जो समय-समय पर उसके माध्यम से वन उपज पर हक का दावा करता हो।

(छ) खाता से अभिभूय -

- (एक) ऐसे भूमि खण्ड से है जिसका भूराजः व पृथक् से निर्धारित हुआ हो और जो एक ही धारणाधिकारी (Tennure) के अधीन धारित हो, और
- (दो) भाड़ेदार या शासकीय पट्टेधारी द्वारा भूमि के सम्बन्ध में एक ही पट्टे या एक ही साथ चलने वाली शर्तों के अधीन यथास्थित भूमि : वामी या राज्य सरकार से धारण किये गये भूमि खण्ड से है।
- (ज) सेवा भूमि के धारक से अभिभूत है गांव के सेवक के रूप में सेवा करने की शर्त पर भूमि धारण करने वाला व्यक्ति।
- (झ) 'अनुज्ञापन विबेता' (Licence Vendor) से अभिभूय, विनिर्दिष्ट वन उपज के सम्बन्ध में उस व्यक्ति से है, जिससे ऐसी वन उपज के फुटकर विबय के लिये धारा 13 के अधीन अनुज्ञापन दी गई हो।
- (ञ) 'फुटकर विबय' (Retail Sale) से अभिभूत है, ऐसे पिरणाम से, जिससे की राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, ऐसी विनिर्दिष्ट वन उपज के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे, अधिक न होने वाली किसी विनिर्दिष्ट वन उपज का विबय।

1. पिरभाषा 'घ' में साल बीज अधि. ब. 1241/21/A/दि. 5.5.75 (राजपड में पृष्ठ 119 दि. 5.5.75 को रू काशित से जोड़ा गया।

- (ट) विनिर्दिष्ट क्षेत्र (Specified Area) से अभिभूय किसी विनिर्दिष्ट वन उपज के सम्बन्ध में, ऐसे क्षेत्र से है, जो कि धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना में ऐसी विनिर्दिष्ट वनोपज के लिये विनिर्दिष्ट किया हो।
- (ठ) विनिर्दिष्ट वन उपज से अभिभूय, विनिर्दिष्ट क्षेत्र के सम्बन्ध में ऐसी वन उपज से है जो धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना में ऐसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये विनिर्दिष्ट की गई हो। (ड) भाड़ेदार (Tenant) से अभिभूत है कोड के चौदहवें अध्याय अधीन भूमि : वामी से मौरूसी काँतकार (Occupancy Tenant) से रूप में भूमि धारण करने वाला व्यक्ति।
- (ढ) 'भूधारी' (Tennure Holder) से अभिभूत है वह व्यक्ति जो राज्य सरकार से भूमि धारण करता हो और जो कोड के उपबन्धों के अधीन भूमि : वामी हो, या भूमि : वामी माना गया हो।
- (ण) 'काँठ' (Kashtha) से अभिभूत है निम्न लिखित वृक्षों की, खड़ी हुई (Standing) या काट कर गिराई गई समः त लकड़ी चाले वह किसी रूयोजन के लिये काटी गई हो, (Fashioned) या खोखली की गई हो (Hollowed) अथवा नहीं -सागौन (Tectona grandis)

साल	(Shorea robusta)
बीजा	(Pterocarpus marsupium),
तिन्सा	(Ouginia dalbergoides),
शीशम	(Delbergia latifolia),
धाबड़ा	(Aenogeissus latifolia),
साज	(Terminalia tomentosa),
महुआ	(Madhuka latifolia),
भिरार	(Chloroxylon swietenia)
करंज	(Pongamia glabra),
तेन्दू	(Diospyros melonoxylon),
लेंडिया	(Lagerströemia parviflora),
सालाई	(Boswellia parviflora),

- (त) इकाई (unit) से अभिभूत है विनिर्दिष्ट क्षेत्र का वह उपखण्ड जो धारा 3 के अन्तर्गत इकाई के रूप में गिठत किया गया हो।
- (थ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जो इस अधिनियम में उपयोग में लाई गई किन्तु पिरभाषित नहीं की

गई हों और जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (ब. 16 वर्ष 1927) में पिरभाषित की गई हो, वही अर्थ होगा जो कि उनके लिये उस अधिनियम में दिया गया है।

धारा 3. ईकाइयों का गठन - राज् य सरकार ूत् येक विनिदरं ट क्षेऽ को उतनी इकाइयों में विभाजित कर सकेगी, जितनी कि वह उपयुक् त समझे, किन् तु वि निदरं ट क्षेऽ को, भिन् न-भिन् न विनिदरं ट वनोपज के लिये भिन् न-भिन् न इकाइयों में विभाजित किया जा सकेगा।

1. मध् य ूदेश विधान ब. 28 वर्ष 1983 जो म. ू. राजपऽ दि. 9 अगः त, 1983 (पृष्ठ 2264) पर ूकाशित के द्वारा संशोधित पिरभाषा एवं वृक्षों की सूची।

धारा 4. अभिकारताओं की नियुक्ति - (1) राज् य सरकार विनिदरं ट, वन उपज के अपनी ओर से बय तथा व् यापार हेतु, भिन् न-भिन् न इकाइयों के लिये समः त या किसी विनिदरं ट वन उपज के लिये एक या अधिक अभिकारताओं की नियुक्ति कर सकेगी, तथा कोई भी ऐसा अधिकतार एक से अधिक इकाइयों के लिये नियुक्ति किया जा सकेगा।

(2) किसी सहकारी सोसायटी, माम पंचायत या जनपद पंचायत को उपधारा (1) के अधीन अभिकारता नियुक् त किया जा सकेगा और उस दशा में जब पूर्वोक् त में से कोई भी अभिकारता की नियुक्ति के लिये नहीं आता (ः वीकार नहीं करता), तब ही किसी अन् य व् यिक्त को अभिकारता के रूप में इस ूकार नियुक् त किया जा सकेगा।

(3) अभिकारताओं के लिये नियुक्ति के सम् बन् ध में निबन् धन एवं शतेर् तथा ूबिया ऐसी होगी, जैसी विहित की जावे।

धारा 5. विनिदरं ट वन उपज के बय या पिरवहन पर निबन् धन - (1) किसी भी क्षेऽ के सम् बन् ध में धारा (1) की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना जारी होने पर :

(क) राज् य सरकार

(ख) इस सम् बन् ध में लिखत रूप से ूाधिकृत किये गये राज् य सरकार के कोई अधिकारी।

(ग) जिस इकाई में वन उपज उगाई हो या पाई जाती हो, उस इकाई से सम् बिन्धत अभिकारता से भिन् न कोई भी व् यिक्त ऐसी विनिदरं ट वन उपज का ऐसे क्षेऽ में न तो बय करेगा और न पिरवहन करेगा।

ः पं टीकरण - 1. बय में वः तु विनमय (Barter) द्वारा बय सम्मिलत है।

ः पं टीकरण - 2. राज् य सरकार या पूर्वोक् त शासकीय अधिकारी, अभिकारता या अनुज्ञप् त विबेता 2या धारा 12(क) के द्वारा किया गया विनिदरं ट वनोपज का बय, इन नियमों के उपबन् धों के उल् लंघन में किया गया बम नहीं समझा जायेगा।

ः पं टीकरण - 3. खाते में कोई िहत न रखने वाले किसी ऐसे व् यिक्त के सम् बन् ध में, जिसने कि ऐसे खाते में उगाई गई या पाई गई, विनिदरं ट वन उपज का संमह का अधिकार अजर्त कर लिया हो, यह समझा जायेगा कि उसने इस अधिनियम के उपबन् धों का उल् लंघन कर ऐसी उपज का बय किया है।

(2) उपधारा (1) में अन् तिवर् ट किसी बात के होते हुए भी -

(क) महुआ से भिन् न वन उपज उगाने वाला, अपनी उपज का पिरवहन उस इकाई के भीतर, जिसमें कि ऐसी वन उपज उगाई जाती हो या पाई जाती हो किसी ः थान से, उस इकाई में के किसी अन् य ः थान को कर सकेगा और महुआ उगाने वाला महुआ को अपे कब् जे में रख सकेगा और उसका पिरवहन उस िजले के भीतर के, जहाँ कि महुआ उगाया जाता हो या पाया जाता हो, किसी ः थान से उस िजले के किसी ः थान को कर सकेगा।

(ख) कोई व् यिक्त ऐसे पिरमाण में, जैसा कि विनिदरं ट किया जावे, अनिधक वन उपज का पिरवहन, ऐसी वन उपज के बय ः थान से उस ः थान तक कर सकेगा जहाँ कि ऐसी उपज उसके (व् यिक्त के) वाः तिवक उपयोग (Bonafide) या उपभोग (Consumption) के लिये अपेक्षित हो।

1. मध् य ूदेश विधान ब. 28 वर्ष 1983 जो राजपऽ दि. 9 अगः त 1983 के पृष्ठ 2264 पर ूकाशित हुआ के द्वारा नवीन धारा 4(2) संः थापित की गई।

2. म.ू. वन उपज (व् यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम वर्ष 1990 से धारा 5 के ः पं टीकरण (2) में संशोधित किया।

(ग) ऐसी विनिदरं ट वन उपज का, जिसका बय राज् य सरकार से या उक् त उपधारा में विनिदरं ट किये गये किसी आफसर या अभिकारता से किसी व् यिक्त के, राज् य के भीतर ऐसे माल के जिसमें कि किसी विनिदरं ट वन उपज कच् चे माल के रूप में उपयोग में लाई जाती हो, विनिमार्ण के लिये या किसी व् यिक्त ने राज् य के बाहर विबय के लिये किया हो अथवा जिसका बय अनुज्ञप् त विबेता ने किया हो, पिरवहन ऐसे व् यिक्त द्वारा, उस सम् बन् ध में ऐसे ूाधिकारी द्वारा ऐसी रीति में, और ऐसी फीस का संदाय किया जाने पर, जैसा कि विहित किया जाए, जारी किये जाने वाले अभिन पास के निबन् धनों तथा शतेर् के अनुसार किया जा सकेगा। विभिन् न आकार की पिरवहन गाडियों के लिये फीस की विभिन् न दरें विहित की जा सकेंगी, और

(घ) कोई भी व्यक्ति, जिससे तत् समय पूर्व तत् किसी विविध के अधीन किसी विनिर्दर वन उपज के सम्बन्ध में किसी वन में निःतार का अधिकार हो, अपने घरेलू उपयोग या उपभोग के लिए ऐसी उपज का, ऐसे परिणाम में तथा ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा कि विहित किया जाए, परिवहन कर सकेगा।

(3) विनिर्दर वन उपज का विवक्षित करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति उसे पूर्वोक्त शासकीय अधिकारी या अभिकर्ता को उक्त इकाई के भीतर निःस्थित किसी भी डिपो में बेच सकेगा;

परन्तु, राज्य सरकार, शासकीय अधिकारी या अभिकर्ता एक बार बेची गई विनिर्दर वन उपज को पुनः बय करने के लिए आबद्ध नहीं होगा।

नोट - (1) निबन्धन केवल तभी लागू होगा जब सम्बन्धित विनिर्दर वनोपज के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी हो। यदि अधिसूचना जारी नहीं होगी, तो निबन्धन लागू नहीं होगा। शासन वि. निरपत्त 1988 MPWN 44 = 1988 मिनसा हा. को नोट 77 पेज 285।

2(धारा 6. विवक्षित)

2(धारा 7. सरकार मूल्य नियत करेगी - राज्य सरकार ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए वह मूल्य नियत करेगी जिस पर कि विनिर्दर वन उपज उगाने वालों से उसके द्वारा या उसके किसी प्राधिकृत आफसर या अभिकर्ता द्वारा विनिर्दर वन उपज का बय किया जाएगा :

परन्तु विभिन्न-विभिन्न इकाईयों के लिए विभिन्न-विभिन्न मूल्य नियत किये जा सकेंगे और ऐसा करने में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाएगा :

(क) विनिर्दर वन उपज के मूल्य जो इकाई में समाविष्ट क्षेत्र के संबंध में पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान वृद्धि रहे हों या इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अधीन नियत किये गये हों;

(ख) इकाई में की वन उपज की क्वालिटी,

(ग) इकाई में उपलब्ध परिवहन सुविधायें,

(घ) परिवहन का खर्च, और

(ङ) इकाई में वृद्धि अकुशल मजदूरों की मजदूरी का सामान्य षःतर।

धारा 8. डिपो का खोला जाना तथा मूल्य सूची आदि का डिपो पर प्रकाशन - प्रत्येक इकाई में ऐसी संख्या में, तथा ऐसे स्थानों पर, जिनको कि राज्य सरकार, विनिर्दर वन उपज उगाने वालों की सुविधा का विचार करते हुए निर्देश दे, डिपो (बय के निः) निःस्थापित किये जावेंगे और विनिर्दर वन उपज की मूल्य सूची, जो कि धारा 7 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत की गई हो, तथा काम काज के घण्टे उस सूचना फलक, पर, प्रमुख रूप से सम्प्रदर्शित (Displayed) किये जावेंगे, जो कि उस प्रयोजन के लिये प्रत्येक ऐसे डिपो में रखा गया है।

धारा 9. राज्य सरकार या अभिकर्ता विनिर्दर वनोपज का बय करेगा - (1) राज्य सरकार या उसका प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता काम काज के घण्टों में डिपो में विवक्षित के लिए लाई गई विनिर्दर वन उपज को धारा 7 के अधीन नियत किये गये मूल्य पर बय करने के लिए बाध्य होगा।

परन्तु राज्य सरकार या उसके प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता को यह षःवतन्त होगी कि वह किसी भी ऐसी विनिर्दर वनोपज का बय करने से इंकार कर दे, जो कि उसकी राय में उपभोग के प्रयोजन के लिये या विनिर्माण के हेतु कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाने के लिए या व्यापार के लिये उपयुक्त न हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के परन्तु के अधीन किसी प्राधिकृत अधिकारी या अधिकर्ता द्वारा उसकी विनिर्दर वनोपज के अःवीकार किये जाने के कारण व्यथित हो, ऐसी अःवीकृति के पन्िह दिन के भीतर, ऐसी इकाई पर जिसमें कि विनिर्दर वन उपज लाई गई हो या पाई गई हो, अधिकारिता रखने वाले वन खण्ड का भार साधक अधिकारी या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा सशक्त किये गये अन्य अधिकारी को मामला निर्दर कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर, यथास्थित वन खण्ड का भार साधक अधिकारी या ऐसा अन्य अधिकारी विहित रीति में जाँच करेगा, और सम्बन्धित पक्षकारों को सुनने के पचात्, ऐसे आदेश पारित करेगा जैसे कि वह ठीक समझे और उस दशा में जब कि वह विनिर्दर वन उपज के अःवीकार किये जाने को अनुचित समझे, तो वह

(क) यदि वह षःनगत विनिर्दर वन उपज को अब भी उस विनिर्माण के लिये, जिसमें ऐसी विनिर्दर वन उपज उपयोग में लाई जाती हो, या व्यापार के लिये उपयुक्त समझता हो, यथास्थित प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता को उसका बय करने का निर्देश दे सकेगा और व्यथित व्यक्ति को ऐसा अतिरिक्त प्रतिकार, जैसा कि वह उचित समझे, और जो विनिर्दर वन उपज के लिये देय मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक न हो, देवा सकेगा।

(ख) यदि वह समझे कि षःनगत वन उपज इस बीच, उस विनिर्माण के लिये, जिसमें कि ऐसी वन उपज उपयोग में लाई जाती हो, या व्यापार के लिये अनुपयुक्त हो गई है, यह निर्देश दे सकेगा कि व्यथित व्यक्ति को किसी ऐसी रकम का, जो कि उपधारा (1) के अधीन उसको ऐसी उपज के लिये देय मूल्य से कम न

हो, तथा ऐसे व्यक्ति द्वारा उठाई गई हानि के लिये नुकसानी के रूप में ऐसे अतिरिक्त तूटकर का जैसा कि वह उचित समझे और जो ऐसे मूल्य का बीस प्रतिशत से अधिक न हो के भुगतान का आदेश दे सकेगा।

(4) इस धारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि, यदि राज्य सरकार या उसके प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता को यह विचार करने का कारण हो कि विषय के लिए तूट की गई उपज राज्य सरकार के वनों की भूमियों की है, तो वह उसको अधिकार में लेने और केवल ऐसे संमहण सम्बन्धी प्रभारों का यदि कोई हो, जैसे कि राज्य सरकार समय-समय पर अवधारित करे, संदाय करने में कोई रुकावट आती है :

1.

म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम 2009 (ब. 11 वर्ष 2009) द्वारा संशोधित। म.प्र. राजप. (असाधारण) दि. 3.8.09 को पृष्ठ 781-782 पर प्रकाशित।

परन्तु किसी विवाद की दशा में खंडीय वन अधिकारी, या ऐसा अन्य अधिकारी जो कि उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किये गये रूप में इस सम्बन्ध में विशेष रूप में (Specifically) सशक्त कर दिया जावे, उसमें उपबोधित रीति में उसे सुनेगा और उसका निपटारा करेगा।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासन वन विभाग अधिसूना ब. 4247/दस 69 दिनांक 1 अगस्त, 1969 राज्य शासन वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 की धारा 9 उपधारा (2) द्वारा रूढ़ित शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त तत्पिरेक्ष्य अधिकारियों को (वन उपज के त्पिरेक्ष्य अधिकारियों सहित) उक्त धारा की उपधारा (2) के आयोजन के लिये सशक्त किया है।

धारा 10. रिजःशीकरण - विनिर्दिष्ट वन उपज को उगाने वाला रूढ़ित व्यक्ति, यदि यह सम्भावना हो कि वर्ष के दौरान उसके द्वारा उगाई गई वन उपज का परिमाण, ऐसे परिमाण से, जो कि विहित किया जाए, अधिक हो जायेगा, तब वन उपज को विहित रीति में रिजःशीकृत करा लेगा।

धारा 11. विनिर्दिष्ट वन उपज के निम्नार्थों, व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं का रिजःशीकरण - (1) रूढ़ित निम्नार्थों जो किसी विनिर्दिष्ट वन उपज को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाता है, और रूढ़ित व्यापारी या कोई उपभोक्ता, जिसका यथास्थित वाणिज्यिक उपयोग (Use), आवश्यकता (Requirement) या उपभोग (Consumption) ऐसे परिमाण से, जो विहित किया जाए, से अधिक हो, तो ऐसी कालाविध के भीतर, ऐसी फीस के संदाय पर, तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाय, तब वन उपज को रिजःशीकृत करा लेता।

(2) ऐसा रूढ़ित निम्नार्थ, व्यापारी या उपभोक्ता, ऐसी घोषणाएँ, लेखे तथा विवरणियाँ ऐसे प्रारूप में, तथा ऐसे प्राधिकारी को, ऐसे अनुरोधों पर, जो कि विहित किये जावे, पत्र तैयार करेगा।

टिप्पणी - (1) हसबंस लाल वि. म. प्र. राज्य (M.P.L.J. 1983 नोट 7) में यह निर्णय लिया गया है कि इस अधिनियम की धारा 11 में वन मण्डलाधिकारी को विनिर्दिष्ट वन उपज के निम्नार्थों का पंजीयन करने के लिए विधिक अधिकार प्राप्त हैं। वन मण्डलाधिकारी को शासकीय आदेश के द्वारा विधिक प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने से रोका नहीं जा सकता है।

धारा 12. विनिर्दिष्ट वन उपज का वयन - इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा या उसके अधिकारी या अभिकर्ता द्वारा बय की गई विनिर्दिष्ट वन उपज ऐसी रीति में जैसी राज्य सरकार निर्देश दे बच दी जायेगी या उसका अन्यथा वयन कर दिया जायेगा।

धारा 12 (क) विनिर्दिष्ट व्यापारी या उपभोक्ता द्वारा अतिरिक्त विनिर्दिष्ट वन उपज का पुनः विषय - (1) कोई भी ऐसी निम्नार्थ, जो किसी वन उपज का उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है या विनिर्दिष्ट वन उपज का कोई व्यापारी या उपभोक्ता जिसके पास ऐसी उपज उसके उपयोग, आवश्यकता या उपभोग के पत्रातिरिक्त बची रह जाती हो, उसका पुनः विषय राज्य सरकार की या राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किये गये किसी आफसर (जो इस धारा में इसके पत्रातिरिक्त आफसर के नाम से निर्दिष्ट है) की अनुज्ञा के बिना नहीं करेगा। ऐसा निम्नार्थ, व्यापारी या उपभोक्ता जो अपने पास अतिरिक्त बच रही विनिर्दिष्ट वन उपज को बेचने का आशय रखता हो, अनुज्ञा के लिए राज्य सरकार या प्राधिकृत आफसर को लिखत में आवेदन करेगा जिसमें-
(एक) बेची जाने की आशयित विनिर्दिष्ट वन उपज के परिमाण का,
(दो) उस दर का जिस पर ऐसी उपज विषय हेतु प्रस्तावित की जाती है, और
(तीन) उस व्यक्ति का जिसको ऐसी प्रस्तावना की गई है। तब तौर पर कथन किया जायेगा।

1.

धारा 12(क) म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन अधि. 1986 (15 वर्ष 87) जो राजप. दि. 24.1.87 पृष्ठ 322-323 पर प्रकाशित द्वारा जोड़ी गई।

(2) विनिर्दिष्ट वन उपज का ऐसा कोई भी रिजःशीकृत निम्नार्थ, व्यापारी या उपभोक्ता, जो उपधारा (1) में विनिरत ऐसी वन उपज का बय करने का आशय रखता हो, उसका बय राज्य या प्राधिकृत आफसर की लिखत अनुज्ञा के बिना नहीं करेगा। ऐसा रिजःशीकृत निम्नार्थ, व्यापारी या उपभोक्ता अनुज्ञा के लिये राज्य सरकार या प्राधिकृत आफसर को लिखत आवेदन करेगा, जिसमें विवेक का नाम बय की जाने वाली ऐसी वन उपज के परिमाण का तथा उसके लिए तय पाई गई दर का तब तौर पर कथन किया जाएगा।

(3) विनिर्देश ट वन-उपज का पुनर्वर्णन करने के लिए उपधारा (1) अधीन आवेदन पत्र तथा ऐसी विनिर्देश ट वन उपज का ब्य करने के लिए उपधारा (2) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर राज्य सरकार या प्राधिकृत आफसर, बेता द्वारा ऐसी फीस का जो विहित की जाय, (1)..... भुगतान किया जाने पर दोनों को लिखत में अनुज्ञा दे सकेगा।

टिप्पणी - (1) माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खंडपीठ भोपाल ने राम जुड़ावन वि. वन संरक्षक भोपाल के करण पर यह निर्णय दिया है कि याचिकाकर्ता तथा शासन के बीच भारतीय संविधान के अनुच्छेद 299 के अधीन संविदा का पालन नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में राज्य शासन को होने वाली क्षति की वसूली भूराज: व के बतौर वसूल की जाने योग्य नहीं है। कारण कि दोनों पक्षों के बीच संविदा हुई ही नहीं तथा ऐसे करण पर वन अधिनियम की धारा 82 अंक ट नहीं होती। (मध्य प्रदेश वीकली नोट्स 1980 पाटर् बमांक 303)

टिप्पणी - (2) धारा 2(5) तथा 12 पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ने निर्णय दान किया है कि राज्य शासन साल के बीज के तेल निकालने वाले उद्योग के सम्बन्ध में नई नीति घोषित करते समय, नई एवं पुरानी यूनिट के सम्बन्ध में आरक्षण की नीति अपना सकती है। राज्य शासन के द्वारा राज्य की 190 खंड को मध्य प्रदेश : टेट सहकारी, मार्केटिंग फेडरेशन के लिये सुरक्षित रखने की नीति को विधिमान्य माना।

(देखें - म.प्र. आइल एक् सटेक्शन प्रायवेट लि. वि. म.प्र. राज्य व अन्य, M.P.L.J. 1983 पृष्ठ 579)

धारा 13. वन उपज का फुटकरा विबय - (1) कोई भी व्यक्ति किसी विनिर्देश ट वन उपज के फुटकर विबय में इस धारा के अधीन मन्जूर की गई अनुज्ञप्ति के अधीन ही : वय को लगावेगा अन्यथा नहीं।

(2) राज्य शासन, राज्य के भीतर, विनिर्देश ट वन उपज के फुटकर विबय को सुगम बनाने के लिये, उतने व्यक्ति को अनुज्ञा दान कर सकेगी, जितने कि वह उपयुक्त समझे।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो कि विनिर्देश ट वनोपज के फुटकर विबय में : वय को लगाना चाहता हो, ऐसे प्रारूप में ऐसे प्राधिकारी को, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाये, आवेदन पत्र देगा।

(4) विहित अधिकारी, ऐसा आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर तथा ऐसी फीस के संदाय पर, जो कि विहित की जाये, ऐतिबन्धनों (Terms) तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, जो कि विहित की जाये, अनुज्ञप्ति मन्जूर कर सकेगा या उसका नवीनीकरण कर सकेगा।

धारा 14. शक्तियों का प्रत्यायोजन - राज्य सरकार, आदेश द्वारा, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन अपनी शक्ति या कृत्यों में से कोई भी शक्ति या कृत्य सहायक वन संरक्षक से अनिवार्य रूप से आदेश या प्राधिकारी (Authority) को प्रत्यायोजित (Delegate) कर सकेगी, जो कि उसे ऐसी शर्तों से तथा ऐतिबन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसे कि राज्य सरकार आदेश में विनिर्देश ट करे, प्रयोग में लायेगा या उसका पालन करेगा।

नोट - मध्य प्रदेश शासन ने इस धारा के अनुवर्तनानुसार अधिकृत किया है - ब. 4248/X/69 दि. 1 अग: त, 1969 मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में उल्लिखित अपनी शक्तियों को, अनुसूची के कालम (3) तत् : थानी प्राधिकारियों में विनिर्देश ट आफसरों को प्रत्यायोजित (Delegate) करता है जो उक्त सूची के कालम (4) में विनिर्देश ट शर्तों तथा ऐतिबन्धनों, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए उन्हें प्रयोग में लावेंगे।

बमांक	शक्तियाँ	आफसर	शर्त तथा ऐतिबन्धन
1.	अथवादेश की धारा (3) के अधीन वन उपज, इकाई गिठत करने की शक्ति।	वन संरक्षक वन उपज भोपाल	इस शक्ति का प्रयोग राज्य शासन की पूर्ण मन्जुरी से किया जावेगा।
2.	अथवादेश की धारा 4 के अधीन अभिकर्ताओं को नियुक्ति तथा नियुक्ति रद्द करने की शक्ति	क्षेत्रीय वृत्त के प्रभारी वन संरक्षक	इस शक्ति का प्रयोग राज्य शासन की पूर्ण मन्जुरी से किया जावेगा।
3.	अथवादेश की धारा 8 के अधीन डिपो खोले जाने के निर्देश देने की शक्ति	खंडीय वन अधिकारी (वन मण्डलाधिकारी)	
4.	अथवादेश की धारा 19 (1) के अधीन अपराधों का प्रशमन की शक्ति	क्षेत्रीय वृत्त के प्रभारी वन संरक्षक तथा खण्डीय वन अधिकारी (वन मण्डलाधिकारी)	

(म. प्र. राजपत्र दि. 1-8-69 पृष्ठ 1917-18 में प्रकाशित)

(2) क. 6880/69 दिनांक 23 अक्टूबर, 1969 (म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 23 अक्टूबर 1969 में प्रकाशित) के द्वारा शासन ने धारा 5 (ख) के अधीन विनिर्देश ट वन उपज को ब्य करने के लिये वन रक्षक तथा उससे उच्च पद के सम: त वन अधिकारियों को इस खण्ड के प्रयोग के लिये प्राधिकारी नियुक्त किया है।

(3) बर्मांक 4247/अ/दस/69 दिनांक 1 अग: त, 1969 (म. पू. राजपऽ दिनांक 1-8-69 पृष्ठ 1917 में लूकाशित) के द्वारा राज् य शासन ने धारा 5(1) के अन् तर्गत सम: त वन अधिकाऱियों को उनके सम् बिन्धत क्षेत्राधिकारों में उक् त धारा के िलये लूाधिकृत िकया गया है।

धारा 15. अधहरणीय सम् पित्त की तलाश, अभिमहण और उसके िलये लूबिया - (1) कोई वन अधिकारी, जो राज् य शासन द्वारा अधिसूचित िकया जावे या कोई सहायक उपनिरीक्षक पुलिस से अनम् न ौणी का कोई अधिकारी, अधिनयम या उसके अधीन बनाये गये िनयमों के उपबन् धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, या ः वयं का यह समाधान करने की दृष्टि से िक उक् त उपबन् धों का अनुपालन िकया गया है -

1(1) िविनिदर् ट वन उपज के परिवहन के िलये उपयोग में लाये गये या लाये जाने के आ शियत िकसी व् यिक्त (Person), नाव, गाड़ी (Vehicle) या पाऽ (Receptable) को रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा िकसी ः थान में लूवेश कर उसकी तलाशी ले सकेगा।

2(1) जब यह िवै वास करने का कारण हो िक िकसी िविनिदर् ट वनोपज के बारे में इस अधिनयम के अन् तर्गत कोई अपराध िकया है, तब ऐसा कोई वन अधिकारी, जो राज् य सरकार द्वारा अधिसूचित िकया जावे या सहायक उपनिरीक्षक से अनम् न ौणी का कोई पुलिस ऑफसर ऐसी िविनिदर् ट वनोपज को, ऐसे सम: त औजारों, नावों, गाड़ियों, र: सों, जंजीरों या िकन् हीं अन् य व: तुओं सहित अभिमहीत कर सकेगा िजसका िक उपयोग इस अधिनयम के उपबन् धों के अधीन ऐसा अपराध करने में िकया है।

नोट - (1) म. पू. शासन (वन िवभाग की अधि. ब. 15-1-87-द-3(1)/(2) दिनांक 26.12.90 से तथा 15(1) तथा 15(2) के अन् तर्गत सम: त वन अधिकाऱियों को कायर्वाही करने हेतु अपने क्षेत्राधिकारी में अधिकृत करता है।

(2) म. पू. शासन, वन िवभाग, अधि. ब. 18.7.85-दस-3(2) दि. 20.8.87 से धारा 15(1) तथा 15(2) के अन् तर्गत कायर्वाही करने हेतु सहायक उपनिरीक्षक पुलिस से अनम् न पुलिस अधिकाऱियों को अधिकृत करता है।

(3) इस धारा के अधीन िकसी सम् पित्त का अभिमहण (Seize) करने वाला कोई ऑफसर या व् यिक्त ऐसी सम: त सम् पित्त पर यह उपदिशर्त करने वाला िचन् ह लगायेगा, िक उसका इस लूकार अभिमहण िकया गया है और अभिमहीत की गई सम् पित्त को यथाशक् य शीय सहायक वन संरक्षक से अनम् न ौणी के ऑफसर के, िजसे राज् य सरकार ने अधिसूचना द्वारा, इस सम् बन् ध में लूाधिकृत िकया हो (जो इसमें इसके पँ चात् लूा िधिकृत ऑफसर के नाम से िनिदर् ट है) समक्ष पेश करेगा या जहाँ परिमाण या लूपुंज (Bulk) को, अन् य व: तिवक किठनाई कोध यान में रखते हुए, यह साध् य न हो िक अभिमहीत की गई सम् पित्त को लूाधिकृत अधिकारी के समक्ष पेश िकया जा सके, जहाँ वह अभिमहण की बाबत िरपोर्टर लूाधिकृत ऑफसर को करेगा या जहाँ अपराधी के िवरुद्ध दिण्डत कायर्वाहियाँ तुरन् त करना आशियत हों, वहाँ ऐसे अभिमहण की िरपोर्टर, उस मिज:शेट को करेगा जो उस अपराध का िवचारण करने की अधिकाऱिता रखता हो, िजसके िक कारण अभिमहण िकया गया है :

ब. एफ. 26-2-2003-दस-3- मध् यूदेश वन उपज (व् यापार िविनियमन) अधिनयम, 1969 (ब. 9 सन् 1969) की धारा 15 की उपधारा (1) तथा (3) द्वारा लूदत् त शिक्तियों को लूयोग में लाते हुए तथा इस िवभाग की अधिसूचना ब. 18-1-87-दस-3(1) दि. 26 दि. दसम् बर 1990 को लूकाशित हुई है, जो "मध् यूदेश राजपऽ (असाधारण)" में दिनांक 28 दि. दसम् बर 1990 को लूकाशित हुई है, राज् य सरकार एतद्द्वारा क्षेत्रीय उप संभाग का लूभार रखने वाले सम: त अधिकाऱियों, क्षेत्रीय वन संभाग का लूभार रखने वाले अधिकाऱियों, राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक तथा अभ् यारण् य के अधीक्षक को उपधारा (3) के लूयोजन के िलए लूाधिकृत अधिकारी के रूप में लूाधिकृत करती है।

परन् तु जब िविनिदर् ट वन उपज, िजसके बारे में ऐसा अपराध िकये जाने का िवै वास िकया जाता है सरकार की सम् पित्त है और अपराधी अज्ञात है, तब यदि आफसर परि:थितियों के बारे में िरपोर्टर अपने पदीय विरं ठ को दे देगा तो पर्यार्प त होगा।

2(3-a) रेंजर से अनम् न रैंक का कोई वन अधिकारी, िजसने या िजसके अधीन: थ ने यथा

1. म. पू. वन उपज व् यापार िविनियम (संशोधन) अधिनयम 1990 धारा 15(1) तथा 12(2) संशोिधित।

2. म. पू. अधि. ब. 14 वर्ष 2007 (म. पू. वनोपज व् यापार िविनियम (संशोधन अधिनयम) 2006 द्वारा 3अ तथा 5-अ जोड़ा गया।

अधहरणीय कोई औजार, नाव, गाड़ी, र: से, जंजीर या कोई अन् य व: तु अभिमहीत की हैं, इस लूकार अभिमहीत संपित्त को अधहरण का ओदश करने वाले लूाधिकृत अधिकारी या उस मिज:शेट, जो उस अपराध का, िजसके कारण अभिमहण िकया गया है, िवचारण करने की अधिकाऱिता रखता हो, के समक्ष जब ऐसा अपेिक्षित हो, पेश करने हेतु ऐसे अधिकारी द्वारा यथा लूाक् किलत ऐसी संपित्त के मूल् य के दुगुने के बारबर रकम की लूतिभूित का ऐसे लूरूप में, जैसा िक िविहत िकया जाए, उसके ः वामी द्वारा िनं पादन करने पर िनमुर्क् त कर सकेगा।"

(4) उपधारा (6) के अधीन रहते हुए जहाँ लूाधिकृत ऑफसर का, यथा िंथित िविनिदर् ट वनोपज अपने समक्ष पेश िकये जाने पर या अभिमहण के बारे में िरपोर्टर के लूाप त होने पर यह समाधान हो जाता है, िक उसके बार में अपराध िकया गया है, तो वह िलिखत आदेश द्वारा और अभिलिखत िकये जाने वाले कारणों से उस िविनिदर् ट वन उपज को जो इस पकार अभिमहीत की गई है, सम: त औजारों, गाड़ियों, नावों, र: सों, जंजीरों, अन् य िकसी अन् य व: तुओं के साथ िजनका िक उपयोग ऐसे अपराध करने में िकया गया है अधिहत कर सकेगा। अधिकरण के आदेश की एक

रूति, बिना असम्पत्ति के विलम्ब के, वृत्त के प्रभारसाधक अधिकारी को भेजी जावेगी, जिसके क्षेत्र में वन उपज अभिमहीत की गई है।

(5) उपधारा (4) के अधीन किसी सम्पत्ति के अधिग्रहण (Confiscate) करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जावेगा जब तक कि प्राधिकृत अधिकारी -

(क) सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिये कार्यवाहियाँ शुरू किये जाने के बारे में सूचना उस अपराध का, जिसके कारण अभिमहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मिजिस्ट्रेट को विहित प्रारूपों में भेज दें।

(ख) उस व्यक्ति को, जिससे वह सम्पत्ति अभिमहीत की गई, तथा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसके बारे में प्राधिकृत अधिकारी को यह सूचित होता हो कि उसका ऐसी सम्पत्ति में कोई हिस्सा है, लिखित सूचना नहीं देता।

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, जो तात्कालिक अधिग्रहण के विरुद्ध, ऐसे व्यक्तिगत तत्त्वों के भीतर, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जावे, अभिवादन करने का अवसर नहीं दे देता, और

(घ) अभिमहण करने वाले अधिकारी या व्यक्ति की तथा उस व्यक्ति या व्यक्तियों की, जिसे या जिन्हें खण्ड (ब) के अधीन सूचना दी गई है, सुनवाई उस प्रयोजन के लिये नियत की जाने वाली तारीख को नहीं कर लेता।

15-क) जहाँ मामले की अधिकारिता रखने वाला प्राधिकृत अधिकारी अभिमहण या अन्य वेशण में व्यय अन्य तमर: त है वहाँ अगला उच्च प्राधिकारी इस धारा के अधीन कार्यवाहियों का संचालन करने के लिए उसी रैंक के किसी अन्य अधिकारी के मामले अंतर्गत कर सकेगा।

(6) उपधारा (4) के अधीन किन्हीं औजारों, गाड़ियों, नावों, र: सों, जंजीरों या किन्हीं अन्य व: तुओं के (जो अभिमहीत की गई विनिर्दिष्ट वनोपज से भिन्न हों) अधिग्रहण का कोई आदेश नहीं किया जावेगा यदि उपधारा (5) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति प्राधिकृत अधिकारी के समाधान रूप में यह साबित कर देता है कि किन्हीं औजारों, गाड़ियों, नावों, र: सों, जंजीरों या अन्य व: तुओं का उपयोग उसकी जानकारी या मौनानुकूलता के बिना या यथास्थित उसके नौकर या अभिकर्ता की जानकारी या मौनानुकूलता के बिना किया गया था और यह कि इस अधिनियम के अधीन के किसी अपराध के किये जाने के लिए पूर्वोक्त व: तुओं के उपयोग को रोकने के लिए सम: त व्यक्तिगत तत्त्वों और आवँयक पूर्व सावधानियाँ बरती गई थी।

1. म.प्र. अधि. ब. 14 वर्ष 2007 (म.प्र. वनोपज व व्यापार विनियम (संशोधन अधिनियम) 2006 द्वारा 3A तथा 5-A जोड़ा गया।

2. म.प्र. वन उपज व व्यापार विनियम (संशोधन) अधिनियम 2009 की धारा (3) (4) से संशोधित।

16-क. अधिग्रहीत वन उपज या कोई अन्य सम्पत्ति, यदि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नलिखित किये जाने हेतु आदेशित की गई हो, तो प्राधिकृत अधिकारी के आदेश की अपील प्राधिकारी द्वारा पुष्टि होने तक या धारा 15-क के अधीन यथा विनिर्दिष्ट उसके द्वारा "वैरणा" से कारवाई प्रारम्भ करने की कालाविधि का अवसान होने तक, इनमें से जो भी पूर्वर्त हो, निरंतर अभिरक्षा के अधीन बनी रहेगी।

17) इस धारा के अन्तर्गत तलाशी एवं जप्ती में दण्ड प्रवर्धन संहिता 1973 (ब. 2 वर्ष 1973) की धारा 102, 103 के तलाशी एवं जप्ती सम्बन्धी प्रावधान, जहाँ तक लागू हो, लागू होंगे।

धारा 15. क. प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील - (1) प्राधिकृत अधिकारी के किसी आदेश से व्यक्ति कोई व्यक्ति, आदेश किये जाने की तारीख से तीन दिनों के भीतर, या ऐसी आदेश सम्बन्धित तथ्य की सूचना उसे नहीं दी गई हो, तो ऐसे आदेश की जानकारी होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर, उस वन वृत्त के, जिसमें वह वन उपज अभिमहीत की गई हो, वन वृत्त के प्रभारसाधक अधिकारी (जो इसमें इसके पश्चात् अपील अधिकारी के नाम से विनिर्दिष्ट है) को लिखित में अपील कर सकेगा, जिसके साथ ऐसी फीस दी जायेगी और जो ऐसे रूप में होगी जैसे कि विहित किया जाये और उसके साथ प्राधिकृत अधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न होगी।

पं टीकरण - (1) इस उपधारा में विनिर्दिष्ट तीस दिनों की कालाविधि की संगणना करने में वह समय अपविजर्त कर दिया जावेगा जो प्राधिकृत अधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित रही हो।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपील प्राधिकारी, उस दशा में जबकि उसके समक्ष कोई अपील न की गई हो, अभिमहण करने वाले अधिकारी को, या व्यक्ति को, और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को जिसके अन्तर्गत अपीलाधीन यदि कोई हो, भी आता है) जिसका कि अपील प्राधिकारी की राय में अधिग्रहण के आदेश से प्रतिकूलताभावित होना संभाव्य है, वैरणा से की जाने वाली कार्यवाही की सूचना प्राधिकृत अधिकारी के आदेश की प्रति, उसे प्राप्त होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर वैरणा (Suo-moto) से दे सकेगा, और अपील के ज्ञापन के पेश किये जाने की दशा में, वह अपील की सुनवाई की सूचना उक्त व्यक्ति को देगा, और मामले का अभिलेख मंगा सकेगा :

परन्तु अपील की कोई औपचारिक सूचना, अपीलाधीन, अभिमहण करने वाले कोई अधिकारी या व्यक्ति को और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति, जिसका कि पूर्वोक्त तानुसार प्रतिकूलत: प्रभावित होना संभाव्य है, में से उसको दिया जाना आवँयक नहीं होगा जो सूचना का अधिप्राप्त (waive) कर दे या जिसे अपील की सुनवाई की तारीख, प्राधिकारी द्वारा, किसी अन्य रीति में सूचित की जा सकती हो।

(3) अपील ूाधिकारी, अपील िकये जाने की, ः वूेरणा से की जाने वाली कायर्वाही िकये जाने के बारे में ूाधिकृत ऑफिसर को िलिखत सूचना देगा।

(4) अपील अधिकारी, अधिहरण की िवषय-वः तु की अभिरक्षा, उसके पिररक्षण (Preservation) या व् ययन (Disposal)(यिद आवँ यक हो) के िलए अंतरिम (Interim) ः वरूप के ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे िक उसे, उस मामले की पिरिःथितयों में न् याय संगत या उचित ूतीत हों।

1. म.ू. वनोपज (व् यापार िविनयमन) संशोधन अधिनियम 2006 (ब. 14 वर्ष 2007) से िनयत 15(र) संशोधित। (धारा 6- 'अ' जोड़ी गई)

2. म.ू. वनोपज (व् यापार िविनयमन) संशोधन अधिनियम 1990 से धारा 15-(7) जोड़ी गई।

3. म.ू. वन उपज (व् यापार िविनयमन) संशोधन अधिनियम 2009 की धारा (4) द्वारा संशोधित।

(5) अपील ूाधिकारी, मामले की ूकृति या अन् तमर्ः त जितलताओं को ध् यान में रखते हुए, अपील के पक्षकारों, को उनका ूितिनिधत् व, उनके अपने-अपने िविध व् यवसायियों द्वारा िकये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(6) अपील की या ः वूेरणा से की जाने वाली कायर्वाही की सुनवाई के िलये िनयत की गई तारीख को, या ऐसी तारीख को, िजसके िलये रखी जावे, अपील ूाधिकारी अभिलेख का पिरशीलन (Peruse) करेगा और यिद अपील के पक्षकार यिद ः व् यं उपिःथत हों तो उनकी सुनवाई करेगा या िलिखत में सम् यक् रूप से ूाधिकृत िकये गये िकसी अभिकर्तार की माफर्त या िकसी िविध व् यवसायी की माफर्त उनकी सुनवाई करेगा और उसके पँ चात् अधिहरण के आदेश की पुष्टि करने, उसे उलटने, या उसे उपांतरित (Modification) करने का आदेश पारित करने के िलये अमसर होगा :

परन् तु कोई अन्तम आदेश पारित करने के पूर्व, अपील ूाधिकारी, यिद अपील के उचित िविनँ चय के िलये या ः वूेरणा से की गई कायर्वाही के उचित िनपटारे के िलये, यह आवँ यक समझा जाता है, िक अतिरक् तर्जाच या तो ूाख् यान या खण् डन करने के िलये पक्षकारों को शपथ-पड फाइल करने के िलये भी अनुज्ञा दे सकेगा और तथ् यों का सबूत शपथ-पड द्वारा िकये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(7) अपील ूाधिकारी, पारिमाणिक ः वरूप (Consequential Nature) के ऐसे आदेश भी पारित कर सकेगा जैसे िक वह आवँ यक समझे।

(8) अन्तम आदेश की या पारिमाणिक ः वरूप आदेश की ूति, अनुपालन के िलये या अपील अधिकारी के आदेश के अनुरूप कोई अन् य समुचित आदेश पारित करने के िलये, ूाधिकृत ऑफिसर को भेजी जावेगी।

धारा 15. (ख) अपील अधिकारी के आदेश के िवरुद्ध सेशन न् यायालय के समक्ष पुनरीक्षण - अपील का कोई भी पक्षकार, जो अपील ूाधिकारी द्वारा पिरत िकये गये अन्तम आदेश से या पारिमाणिक ः वरूप के आदेश से व् यिथत हो, उस आदेश के, िजसके िवरुद्ध आक्षेप िकया जाना इप्सत है, तीस िदन के भीतर, उस सेशन न् यायालय को पुनरीक्षण के िलये याचिका ूः तुत कर सकेगा, िजसके सेशन खण् ड के भीतर अपील ूाधिकारी का मुख् यालय िःथत हो।

ः पं टीकरण - (1) इस उपधारा के अधीन तीस िदन की कालाविध की संगणना करने में वह समय अपविजर्त कर िदया जायेगा जो अपील अधिकारी के आदेशों की ूमाणिक ूति अभूप् त करने के िलये अपेक्षित रहा हो।

(2) सेशन न् यायालय, अपील ूाधिकारी द्वारा पिरत िकये गये िकसी अन्तम आदेश की या िकसी पारिमाणिक ः वरूप के आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उलट सकेगा या उसे उपांतरित कर सकेगा।

(3) पुनरीक्षण में पारित िकये गये आदेश की ूतियाँ अपील ूाधिकारी को तथा ूाधिकृत ऑफिसर को अनुपालन के िलये, या ऐसे अतिरक् त आदेश पारित करने के िलए, या ऐसी अतिरक् त कायर्वाही करने हेतु भेजी जायेगी जैसा िक ऐसे न् यायालय द्वारा िनदेर्शित िकया जाये।

(4) इस धारा के अधीन, िकसी पुनरीक्षण को महण करने (Entertaining), उसकी सुनवाई करने और उसका िविनँ चय करने (Decide) के िलये, सेशन न् यायालय उन् हीं शिक्तियों का ूयोग करेगा और उसी ूबिया का अनुसरण करेगा, िजसका िक ूयोग और अनुसरण वह दण् ड ूबिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन से िकसी पुनरीक्षण को महण करने, उसकी सुनवाई करने, और उसका िविनिश्चय करने के समय करता है।

(5) दण् ड ूबिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन् तिवर् ट िकसी तत् ूितकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन पारित िकया गया सेशन न् यायालय का आदेश अन्तम होगा और उसे िकसी भी न् यायालय के समक्ष ूँ नगत (Called in question) नहीं िकया जाएगा।

धारा 15-ग. कितपय पिरिःथितयों में न् यायालय आद की अधिकांरिता का वर्जन - (Bar) उस अपराध का, िजसके कारण उस सम् पित्त का, जो िक अधिहरण की िवषय-वः तु है, अभिमहण िकया गया है, िवचारण करने की अधिकांरिता रखने वाले मिजःशेट को सम् पित्त के अधिहरण के िलये कायर्वाहियाँ शुरू की जाने के बारे में धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन सूचना ूाप त होने पर, िकसी भी न् यायालय, अधिहरण या ूाधिकारी जो यथािःथित धारा 15, 15, क तथा 15 ख में िनिदर् ट ूाधिकृत ऑफिसर, अपील अधिकारी, सेशन न् यायालय से िभन्न न हो को इस अधिनियम में या तत् समय ूवृत्त िकसी अन् य िविध में अन् तिवर् ट िकसी बात के होते हुए भी उस सम् पित्त के कब् जे, पिरदान, व्

ययन या विवरण के विषय में कोई आदेश करने की अधिकारिता नहीं होगी, जिसके कि बारे में धारा 15 के अधीन कायवाहियाँ शुरू हो गई हैं :

परन्तु सम्पत्ति के वयन (disposal) के लिए कोई आदेश पारित करने के पूर्व, मिज:शेट अपना यह समाधान कर लेगा कि धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन कोई सूचना उसके न्यायालय को या उस अपराध का, जिसके कारण सम्पत्ति का अभिमहण किया गया है। विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त नहीं हुई है।

०: पं टीकरण - (1) जहाँ तत् समय पूर्व किस्ती विविध के अधीन, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने की अधिकारिता दो या अधिक न्यायालयों को हो, वहाँ ऐसी अधिकारिता रखने वाले मिज:शेट के न्यायालयों में से किसी एक को धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन की सूचना प्राप्त हो जाने का यह अर्थ लगाया जायेगा कि उस उपबन्ध के अधीन सूचना सम: त न्यायालयों को प्राप्त हो गई है और अधिकारिता का प्रयोग करने का वर्जन ऐसे सम: त न्यायालयों पर प्रवर्तित हो गई है और अधिकारिता का प्रयोग करने वर्जन ऐसे सम: त न्यायालयों पर प्रवर्तित होगा।

(2) इसमें इसके पूर्व अन्य विवरण कि किसी भी बात के सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायेगा कि वह राज् यसरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किये गये किसी ऑफिसर को इस बात से निवारित करती है कि वह धारा 15 के अधीन अभिमहीत (Seized) की गई किसी सम्पत्ति को तुरन्त निमूर्कृत किये जाने का निर्देश किसी भी समय दें।

धारा 15. घ. सम्पत्ति का अधिहरण जबकि वह उपज सरकार की सम्पत्ति न हो - ऐसी सम: त विनिदरु ट वन उपज, जो दोनों में से उत्तम, सरकार की सम्पत्ति नहीं है, और जिसके विषय में, इस अधिनियम के, या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है, तथा सम: त औजार, नावें, गाड़ियाँ, र: से, जंजीरें या कोई अन्य व: तुएँ, जिसकी उत्तम दशा में उपयोग ऐसा उल्लंघन करने में किया गया है अपराधी को ऐसे उल्लंघन के लिये दोषिसद्ध ठहराये जाने पर धारा 15, 15-क, 15-ख, 15-ग के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अधिहरणीय होगी।

धारा 16. शांति - यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा तो -

(क) वह कारावास से, जो 1 (दो वर्ष) तक का हो सकेगा या जुर्माना से जो 1 (एक) सौ हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

1. म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियम) संशोधन अधिनियम 1990 से नियम 16 में संशोधन।

(ख) उस वन उपज को जिसके सम्बन्ध में ऐसा उल्लंघन किया गया हो, या उसके ऐसे भाग का जैसा कि न्यायालय का उचित ढूँढती हो, सरकार के पक्ष में समपहरण (Forfeit) किया जा सकेगा।

परन्तु यदि न्यायालय की राय हो कि यथा: थित सम्पूर्ण विनिदरु ट वन उपज या उसके किसी भाग के सम्बन्ध के समपहरण का निर्देश देना आवश्यक नहीं है तो वह अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के आधार पर ऐसा करने से विवर्त रह सकेगा।

धारा 17. प्रत्युत्तन का दुर्लक्षण - किसी भी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जो कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने का प्रत्युत्तन करे या उसके उल्लंघन को दुर्लक्षित (Abets) करे तो यह समझा जायेगा कि उसने ऐसे उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

धारा 18. अपराधों का संज्ञान (Cognizance of Offences) - वन खण्ड का भारसाधक अधिकारी से अनमन्य ढीणी के किसी वन अधिकारी द्वारा या किसी अन्य ऑफिसर द्वारा, जो कि इस सम्बन्ध ने राज् य सरकार द्वारा प्राधिकृत कर दिया जाये, उन तथ्यों के सम्बन्ध में, जिनसे कि अपराध बनता हो, की लिखित रिपोर्ट के बिना कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

नोट - मध्य प्रदेश शासन ने अधिसूचना बर्मांक 4247/ब/दस/69 दि. 1 अग: त, 1969 के द्वारा, (जो रापजS दि. 1 अग: त, 1969 में प्रकाशित) धारा 18 के अधीन शिक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सम: त सहायक वन संरक्षक व अतिरिक्त सहायक वन संरक्षकों को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिये अधिकृत किया है।

धारा 19. अपराधों का प्रशमन - (1) राज् य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी वन अधिकारी को इस बात के लिये सशक्त कर सकेगी कि वह -

(क) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके कि विरुद्ध यह युक्तियुक्त संदेह विद्यमान हो कि उसने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है, उस अपराध के लिए, जिसके बारे में यह संदेह है कि उसने ऐसा अपराध किया है, प्रतिकर के रूप में कोई धनराशि प्रतिकृत करे; और

(ख) जब विनिदरु ट वन उपज से भिन्न कोई सम्पत्ति अधिहरणीय होने के कारण अभिगृहीत की गई है, तो समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के आदेश पारित किए जाने के पूर्व किसी भी समय ऐसे अधिकारी द्वारा यथाप्राक् किलत उसके मूल्य का संदाय कर दिया जाने पर, उस सम्पत्ति को निमूर्कृत कर दे;

(2) यथास्थित ऐसी धनराशि, या ऐसे मूल्य या दोनों का ऐसे अधिकारी को संदाय किया जाने पर, संदिग्ध व्यक्ति को, उन् मोचित कर दिया जाएगा और विनिदरु ट वन उपज से भिन्न अभिगृहीत सम्पत्ति, यदि कोई हो, निमूर्कृत कर दी जाएगी और ऐसे व्यक्ति या ऐसी सम्पत्ति के विरुद्ध कोई और कायवाहियाँ नहीं की जाएगी;

(3) कोई वन अधिकारी इस धारा के अधीन तब तक सशक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह रेंजर की रैंक से अनिवार्य रूप से वन अधिकारी न हो, तथा उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अधिकार के रूप में अधिकृत धन की राशि किसी भी मामले में वन उपज के मूल्य के दोगुने से कम की नहीं होगी;

1. म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम 2009 से संशोधित।

परन्तु ऐसी वन उपज के मामले में, जिसके संबंध में कोई अपराध किया गया है, सरकार की सम्पत्ति नहीं है या ऐसी वन उपज के मामले में, जिसका मूल्य एक हजार रुपये से कम है या यदि अपराधी ने प्रथम बार अपराध किया है, तो संदिग्ध व्यक्ति को उन्मोचित किया जा सकेगा तथा वन उपज से विभन्न सम्पत्ति, यदि कोई हो, जो अभिगृहीत की गई है, दस हजार रुपये की राशि के या ऐसी अभिगृहीत सम्पत्ति के मूल्य, जो भी कम हो, के संदाय पर निमुक्त की जा सकेगी; अभिगृहीत वन उपज केवल तब तक ही निमुक्त की जा सकेगी; जब वह, यथास्थित, सरकार की सम्पत्ति नहीं है या जब उसके मूल्य का संदाय कर दिया जाता है।

नोट - (1) म.प्र. शासन ने अधिसूचना ब. 4248/X/65 दि. 1 अगस्त, 1969 के द्वारा इस धारा के अधीन क्षेत्रीय वन संरक्षक तथा खण्डीय वन ऑफिसर को अधिकार प्रत्यापोजित किया है।

टिप्पणी - (1) अपराधों का प्रशमन तभी पूर्ण होगा जब राजीनामा की राशि पटा दी गई हो। विना राशि पटायें अपराध का प्रशमन होने पर तथा बाद में न पटाने पर यह राशि भू. रा. सं. की धारा 155 के अनुवर्त राजः व बकाया के रूप में वसूली योग्य नहीं है। (देखें J.L.J 1978 पृष्ठ 613 प्रेमनारायण किशनलाल वि. म.प्र. राजः) यही फैसला दिनेश कुमार वि. डी.एफ.ओ. में भी दिया गया है। (1948 Weekly notes 54)

(2) अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन अपराधों का प्रशमन करने की शक्ति - समः त सहायक वन संरक्षक (क्षेत्रीय वन सम्भाग) वन्य जीव वन सम्भाग में पदः त क्षेत्रीय अधिकार रखने वाले समकक्ष अधिकारी समः त खण्डीय वन अधिकारी तथा वन्य जीवन सम्भाग क्षेत्रीय संभाग में पदः त समकक्ष ऑफिसर वन्य जीव। राष्ट्रीय उद्यानों पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले वन वृत्त के ऑफिसर।

अध. ब. 26.02.2002-दस-3 दिनांक 5.5.2008 से जोड़ा गया।

धारा 20. सद्भावनापूर्वक किये गये कार्यों के सम्बन्ध में व्यवृत्ति (Saving)- (1) किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी भी ऐसी बात के लिये जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई हो, जिसका इस प्रकार किया जाना आशियत रहा हो, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विविध कार्यवाही प्रोत्तुत नहीं होगी।

(2) राज्य सरकार के विरुद्ध अधिनियम के उपबन्धों के आधार पर या किसी भी ऐसी बात के द्वारा, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई हो या जिसका ऐसा किया जाना आशियत रहा हो, पहुँचाये गये या संभाव्यता पहुँचाये जाने वाले किसी नुकसान अथवा उठाई गई या संभाव्यतः उठाई जाने वाली किसी क्षति के लिये कोई वाद या विविध कार्यवाही प्रोत्तुत नहीं होगी।

धारा 21. नियम बनाने की शक्ति - (म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1986 के द्वारा संशोधित)

(1) राज्य सरकार पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के समः त उपबन्धों को या उसके किसी भी उपबन्ध को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(2) विंशतः और पूर्वमामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल भाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समः त या किन्हीं

विषयों के लिये उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात्

(क) धारा 4 के अधीन अभिकर्ताओं की नियुक्ति सम्बन्धी निबन्धन शर्तें तथा प्रबिधा

(ख)(एक) विनिर्दष्ट वन उपज का वह परिमाण, जिसका कि धारा 5(2) (ख) के अधीन उपभोक्ता द्वारा परिवहन किया जा सकेगा।

(दो) धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन अभिवहन पास के निबन्धन तथा शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए विनिर्दष्ट वन उपज का परिवहन किया जा सकेगा, वह प्राधिकारी जिसके द्वारा तथा वह रीति जिसमें तथा वह फीस जिसका संदाय किया जाने पर ऐसा अभिवहन पास जारी किया जायेगा।

(ग)(एक) धारा 6(3) के अधीन सिमित के कामकाज के संचालन की रीति।

(दो) ऐसे भत्ते जिनके लिये सिमित के सदः य धारा 6(4) के अधीन हकदार होंगे।

(घ) धारा 7 के अधीन मूल्य सूची का प्रकाशन।

(ङ) धारा 9 (3) के अधीन जाँच करने की रीति।

(च)(एक) विनिर्दष्ट वन उपज के परिमाण की धारा 10 के अधीन विहित किया जाना

(दो) धारा 10 के अधीन रिजःशीकरण की रीति।

(छ)(एक) विनिर्दष्ट वनोपज के परिमाण की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन विहित किया जाना।

(दो) वह कालाविध जिसके भीतर, वह फीस जिसके संदाय तथा वह रीति जिसमें धारा 1 की उपधारा

(1) के अधीन रिजःशीकरण किया जायेगा।

- (तीन) वे घोषणाएँ, लेखे तथा विवरणियाँ जो कि धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन ००: तुत की जायेंगी और वह ००रूप िजसमें, वह अफसर िजसे तथा वे अन्तराल िजन पर वे ००:तुत की जावेंगी। (छ-छ)
- धारा 12-क की उपधारा (3) के अधीन वह २राशि िजसका संदाय िकिया जाने पर अनुज्ञा दी जा सकेगी।
- (ज) वह ००रूप िजसमें, वह ००ाधिकारी िजसे, तथा
- (एक) वह रीति िजसमें धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन आवेदन पड िदया जायेगा।
- (दो) अनुज्ञित के जारी िकिये जाने तथा उसके नवीनीकरण के िलये फीस और वे िनबन्धन तथा शतेर् िजनके अध् यधीन रहते हुए धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन ऐसी अनुज्ञित मन् जूर की जायेगी।
- २(ज-ज) धारा 15 की उपधारा 5 के अधीन वह पारूप, िजसमें सम्पित्त के अधहरण की कायर्वाही की सूचना भेजी जावेगी।
- २(ज-ज-ज) धारा 15-क की उपधारा (1) के अधीन वह ००रूप िजसमें अपील की जायेगी तथा वह फीस जो ऐसी अपील के साथ ००: तुत की जायेगी और रूप िजसमें उसका संदाय िकिया जायेगा।
- (झ) कोई अन् य विषय, िजसका इस अधिनियम के अधीन विहित िकिया जाना आवै यक समझा जावे।
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सम: त िनयम विधान सभा पटल पर रखे जावेंगे।
- ३(धारा 22. भारतीय वन अधिनियम के उपबन्ध अन् य विषयों को लागू होंगे-

1. म.०. वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम 1986 (ब. 15 वर्ष 1987) द्वारा जोड़े गये। 2. म.०. (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम 1990 (ब. 16 वर्ष 1990) द्वारा संशोधित। म.०. राजपड (असाधारण) िद. 21.8.90 पृष्ठ 1937-1938 पर ००काशित।

3. म.०. वनोपज (व्यापार विनियमन) संशोधन अधि. (ब. 15 वर्ष 1987) द्वारा संशोधित।

(1) विनिदरं ट वन उपज से सम्बन्धित वे विषय िजनके िलये इस अधिनियम में उपबन्ध नहीं हैं और िजनके िलये उपबन्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927, (1927 का सं. 16) में है, उस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा शासित होंगे।

(2) िकसी अन् य विधि, िनयम या आदेश में, या राज् य के िकसी क्षेड में विविध का ००भाव रखने वाले िकसी अन् य विषय में अन् तिवर् ट कोई भी बात उन विषयों के सम्बन्ध में विनिदरं ट वन उपज को लागू नहीं होगी िजनके िलये इस अधिनियम में अन् तिवर् ट है।

१(धारा 22-क. विनिदरं ट वन उपज की अधिनियम से ००वत् तर्न से अपरिवर्तित करने की शिक्त - (1) राज् य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा यह िनदेश दे सकेगी िक उसमें (अधिसूना में) विनिदरं ट की गई तारीख से कोई वन उपज जो धारा 1 की उपधारा (3) में विणर्त या उसके अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिदरं ट की गई हो, ऐसे क्षेड या क्षेडों के सम्बन्ध में जो िक उक् त अधिसूचना में विनिदरं ट की गई हो, ऐसे क्षेड या क्षेडों के सम्बन्ध में जो िक उक् त अधिसूचना में विनिदरं ट िकिया जाये, विनिदरं ट वन उपज नहीं रहेगी।

(2) राज् य सरकार समय-समय पर एक ऐसी ही अधिसूचना द्वारा, यह िनदेश दे सकेगी िक उसमें (अधिसूचना में) विनिदरं ट की गई तरीक से वह विनिदरं ट वन उपज न रह गई हो, ऐसे क्षेड या क्षेडों के सम्बन्ध में जो िक उस अधिसूचना में विनिदरं ट वन उपज होगी।

(3) उपधारा (1) या (20) के अधीन जारी की गई ००प् चात् शीय विधान सभा के पटल पर रखी जायेगी।

तु येक अधिसूचना उसके जारी िकिये जाने के

धारा 23. िनरसन - मध्य ००देश वन उपज (व्यापार विनियमन) अध् यादेश, 1969 (ब. 9, वर्ष 1969) एतद्वारा िनर: त िकिया जाता है।

न् यायालयीन िनणर्ण

टिप् पणी - (1) सन् तोष कुमार िमौ वि. म.०. राज् य मे न् यायमूर्तिर् ौी सी.पी. सेन ने यह िनणर्ण ००दान िकिया है िक म.०. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 की धारा 15 के अधीन यिद िकसी वन अधिकारी ने शक जप् त िकिया है तो ऐसी जप् ती पुलिस विभाग द्वारा जप् ती नहीं मानी जावेगी तथा ऐसी जप् ती के िलये द.०.सं., 1973 की धारा 457 के ००ावधान लागू नहीं होते हैं।

(2) करोड़ी मल अमवाल वि. म.०. राज् य (म.०. ला. जन. 1988 पृष्ठ 600) में अपराध 18-11-83 को हुआ। इस ०० कारण में वन अधिकारी ने म.प. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम के िनयम 15 के अन् तर्गत अधहरण का आदेश िदया गया। यह आदेश िनयम के विरुद्ध था। तथा इस ००करण में भारतीय वन अधिनियम ब. 16/1927 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे तथा धारा 22 की रोक के कारण भारतीय वन अधिनियम 1927 का संशोधित म.०. अधिनियम 25/1983 (००भावी िदनांक 1-11-1983 को संशोधित) की धारा 52ए को लागू नहीं िकिया जा सकता और वन उपज व्यापार विनियमन (म.०.) अधिनियम 1969 के संशोधन अधिनियम ब. 15/1987 के पूर्वर की अधहरण (Confiscation) की कायर्वाही को उस विशेष अधिनियम के अधीन कायम नहीं रखा जा सका।

(4) ओम ठूकार अमवाल वि. ः टेट म.०. - 1994 (11) म.०. जू युडिशियल रिपोर्टर् 145 में जिःटस यू.एल. भट तथा जिःटस एम.व्. ही. तामः कर डीबी हाईकोर्ट म.०. ने इस मामले के रिफरैन्स के साथ विविध का यथाथर् विव लेषण किया है जिसमें 27, 28 दिसम्बर 1983 की बीच राई का वन अपराध है इसमें हाईकोर्ट ने भारतीय वन अधिनियम 1927 के म.०. संशोधन अधिनियम ब. 25/1983 (रूभावी 1-11-1983) के अधीन यदि अधहरण की कार्यवाही आवैयक समझी जाये तो यान के मालिक को पूर्वर नोटिस तथा सुनवाई का अवसर देकर की जा सकती ऐसा विनिश्चित किया - (पैरा 8) तथा वर्तमान में अधहरण की बिना नोटिस और सुनवाई का अवसर दिये की गई कार्यवाही को अवैधानिक ठहराकर निरःत किया (पैरा 3, 8) 1994 (II) म.०. जे.आर. 145) डाबी हाईकोर्ट (म.०.)।

1. म.०. वनोपज (व्यापार विनियमन) संशोधन ब. 16 वर्ष 1972 की धारा-3 से नियम 22(क) जोड़ा गया।

ः टेट म.०. वि. राकेश कुमार 1994 (1) म.०. जू युडिशियल रिपोर्टर् 368 (जिःटस एस.के. दुबे म.०. हाईकोर्ट) धारा 52 एवं 52-सी (संशोधित अधिनियम ब. 25/1983) के अनुसार न्यायिक मिजःशेट को विविधवत वन अपराध के कारित होने के संदर्भ में वन उपज या यान, उपकरण का अभिमहण, वन अधिकारी द्वारा की जाने तथा अधहरण (Confiscation) की कार्यवाही ठारम्भ करने की सूचना दे दी जिससे उस मामले में न्यायिक मिजःशेट को धारा 457 और 451 दण्ड ठूबिया संहिता 1973 के अधीन कार्यवाही करने की अधिकारिता cease (समाप्त) हो जाती है - जिःटस ए.के. दुबे ने विनिश्चित किया - "The Seizure of the truck by the police officer for the forest offence coupled with the offence under Penal Code or any other enactment, in the opinion of this Court, will not make any difference after the intimation of initiation of proceedings under sec. 52(4) of Confiscation and the jurisdiction will stand ousted of the magistrate concerned to deal with the subject-matter so seized for passing the order for interim or final custody under the provisions of Sec. 451 and 457 Cr P.C." 1994(1) M.P.J.R. 368 para 110(H.C., M.P.) Justice S.K. Dubey);

(1) कन् हैयालाल वि. ः टेट म.०. - 1998 जलाज 94 इस मामले में शक पुलिस द्वारा सीज (Seize) नहीं किया गया था तथा मिजःशेट के सामने पेश नहीं हुआ था। धारा संशोधित 52-C (IF Act) के कारण धारा 451Cr PC की अधिकारिता ousted होनी मानी गई।

(2) अशोक कुमार वि. ः टेट म.०. - बिमनल रिर्व हीजन ब. 59/1989- निनीर्त दि. 13-4-1994 Unreported case में भी यही View किया गया है।

(3) रेंज फारेः ट आफिसर वि. रोडीलाल - 1987 बीमीनल लॉ जनरल 1314 - में करार दिया गया कि जब सेशन्स न्यायालय धारा 52-B(2)(IF Act) के अधीन रिर्व हीजन सुनता है तब बिदकारिता पर रोक हट जाती है जिसमें सेशन्स जज उस आदेश के विरुद्ध रिर्व हीजन आवेदन पर विचार करता है जिसमें अपीलीय आदेश में अपील को निरःत कर अधहरण की धारा 52 (IF Act) में की गई कार्यवाही बहाल रखी गई है।

रिषी नाथ सिंह वि. ः टेट म.०. - 1992 म.०. लॉ जनरल 159 - एक शक वन विभाग ने सीज (Seize) किया था और पुलिस ः टेशन में मामला 353, 186 सहपिठत धारा 34(IPC) में रिजः टर हुआ था किन्तु धारा 52-C(IF Act) की दृष्टि से कन् हैयालाल केस (उपरोक्त) तथा बाबूलाल लोदी वि. ः टेट म.०. - 1987 ज.ला.ज. 423 का अनुसरण करते हुए धारा 451, 457, CrPC की कार्यवाही का अधिकार सुरक्षित नहीं रहना (not saved) माना गया।

ः टेट म.०. वि. कुंवर लाल (1994(1) म.०. वी. नोट 48) - इस मामले में शेक्टर शाली पत्थरों के Slabs ले जाते हुए वन विभाग के ठूाधिकारी ने Seize किया था और मुख् य न्यायिक मिजःशेट को इन्टीमेशन दिया अतः धारा 457CR PC की अजीर् खारिज हुई।

(4) महुआ फूल विनिदर ट वनोपज दि. 12-6-72 से नहीं रहा है।

(5) अन् य विविध लागू न होना - ऐसा लागू न होना आंशिक है, पूर्ण नहीं कन् हैयालाल वि. म.०. राज् य 1988 J.L.J. 94 Such exclusion is partial & not absolute

मिसलेनियस पिटीशन ब. 2875/1983 जबलपुर, के दि. 24.6.88 के निनर्ण अनुसार वन अधिकारी द्वारा वनोपज राजसात करने के आदेश विविध विरुद्ध हैं। अधिनियम में संशोधन अध. (15 वर्ष 1987) के पूर्वर वन अधिकारियों को यह शक्ति नहीं दी है।

(6) अपराध में जप्त वाहन जिसके विरुद्ध राजसात की कार्यवाही चल रही हो, इस कार्यवाही ठारम्भ करने की सूचना न्यायालय को देने के उपरान्त मिजःशेट को द.०.स. की धारा 451-457 के अन्तर्गत शक को सुपुदनमें पर देने की अधिकारिता नहीं रहती है। (रिशीनाथ वि. म.०. राज् य ठू.ब. 163 वर्ष 1991)MPLJ 1992 Page 159.

(7) धारा 15 (i) तथा 15(5) - ठूाधिकृत अधिकारी द्वारा यान के अधहरण की कार्यवाही ठारम्भ की गई। सम्विन्धत मिजः. को ऐसी कार्यवाही ठारम्भ करने की सूचना दी। अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण के अन् यथा किसी भी न्यायालय या अधिकारी को यान छोड़ने की अधिकारिता नहीं है। म.०. राज् य वि. अनल किशोर 1996(i) M.P.W.N. 31